इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर प्रति माह 40 रुपए

(आईएसओ 9000-2015 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

Committed to professional excellence

खंड संख्या 14 | अंक संख्या 7 | फरवरी 2022 | पृष्ठों की संख्या - 10

विजन:

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ ---------- 2
बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ ---------- 3
बैंकिंग जगत की घटनाएँ ---------- 3
विनियामकों के कथन ---------- 4
आर्थिक संवेष्टन ---------- 4
नयी नियुक्तियाँ ---------- 5
विदेशी मुद्रा ---------- 5
शब्दावली ---------- 6
वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी ------- 6
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां --------- 7
संस्थान समाचार ---------- 7
नयी पहलकदमी ---------- 9
बाजार की खबरें ---------- 9

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित /उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

संघीय बजट 2022 की मुख्य बातें

माननीय वित्त मंत्री ने उच्च एवं बढ़ती मुद्रास्फीति और अविरत कोविड अनिश्चितताओं के बीच वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई एक क्षेत्रों के लिए कतिपय उपायों के साथ संघीय बजट 2022 प्रस्तुत किया। डिजिटल रुपए की शुरूआत उक्त बजट की एक महत्वपूर्ण घोषणा थी। वित्त एवं अर्थव्यवस्था से संबन्धित कुछेक मुख्य बातें इसके नीचे प्रस्तुत की जा रही है:

- पूंजीगत व्यय (copex) का लक्ष्य 35.4% बढ़ा कर 5.54 लाख करोड़ रुपए के स्थान पर 7.50 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया।
- आकस्मिक ऋण व्यवस्था गारंटी योजना (ECLGS) सुरक्षा 50,000 रुपए बढ़ाकर 5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई।
- 2022-23 से आरंभ होने वाली ब्लाकचेन-आधारित डिजिटल रुपए की शुरूआत, डिजिटल रुपए की यह शुरूआत 2022 तक की जाएगी।
- प्रतीयमान (virtual) डिजिटल आस्तियों से आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा।
- प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए 48,000 करोड़ रुपए आबंटित।
- सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के श्रेणी-निर्धारण के लिए आगामी 5 वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपए के कार्यक्रम आरंभ किए जाएंगे।
- स्टार्ट-अपों (start-ups) के लिए मौजूदा करगत लाभ/प्रसुविधाएं एक और वर्ष तक बढ़ाए जाएंगे/बढाई जाएंगी।
- 2022-23 में निवेशों को उत्प्रेरित करने के लिए राज्यों को 1 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- वित्तीय समावेशन और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, एटीएमों के माध्यम से खातों तक पहुँच को समर्थ बनाते हुये तथा डाकघरों में खातों और बैंक खातों के बीच निधियों के आनलाइन अंतरण की सुविधा उपलब्ध कराते हुये 1.5 लाख डाकघरों के 100% को कोर बैंकिंग समाधान प्रणाली के तहत लाया जाएगा।
- दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (IBC) में संशोधनों से समाधान प्रक्रिया की कार्यकुशलता में वृद्धि होगी तथा सीमा-पार वाले दिवाला का समाधान करना सुगम हो जाएगा।
- डिजिटल भुगतानों को प्रोत्साहित करने के लिए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक खोले जाएंगे।
- सरकारी अधिप्राप्तियों (procurement) में बैंक गारंटी के प्रतिस्थानी के रूप में प्रतिभू (surety) बाँड़ों को स्वीकार्य बनाया जाएगा।
- अपेक्षाकृत त्वरित विवाद समाधान उपलब्ध कराने के लिए गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उच्च प्रौद्योगिकी (GIFT) नगर में अंतर्राष्ट्रीय विवाचन (arbitration) केंद्र की स्थापना की जाएगी।
- गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय उच्च प्रौद्योगिकी / भारतीय वित्तीय प्रली कूट (IFSC) में घरेलू विनियमन से मुक्त विश्व-स्तरीय विश्वविद्यालय की अनुमति दी जाएगी।
- माता-पिता/अभिभावकों के जीवनकाल अर्थात माता-पिता/अभिभावकों के साठ वर्ष की आयु तक पहुँचने के दौरान भिन्न रूप से असमर्थ आश्रित को वार्षिकी (annuity) एवं एकमुश्त रकम का भुगतान।

भारतीय रिजर्व बैंक ने लेनदेन की ऊपरी सीमा को 200 रुपए तक सीमित करते हुये आफ़लाइन लेनदेनों को अधिक सुरक्षित बनाया

प्रयोक्ताओं के लिए आफ़लाइन भुगतानों को अधिक सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसी रूपरेखा जारी की है जिसमें किसी भी समय किसी भुगतान लिखत पर समग्र सीमा को 2,000 रुपए रखने के साथ किसी आफ़लाइन लेनदेन की ऊपरी सीमा को 200 रुपए तक सीमित कर दिया गया है। आफ़लाइन भुगतान अतिरिक्त कारक अधिप्रमाणन (AFA) के

बिना केवल आमने-सामने वाली विधि से ही किए जा सकते हैं। तथापि, 2,000 रुपए की उपयोग सीमा की पुन: पूर्ति करने हेतु अतिरिक्त कारक अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा जिसकी अनुमति केवल आनलाइन विधि में ही प्रदान की जाएगी। आफ़लाइन भुगतान विधियों को ग्राहक की विशिष्ट सहमति से ही समर्थ किया जा सकता है। कार्डों के मामले में इस प्रकार के लेनदेनों की अनुमति संपर्करहित लेनदेन चैनल को अपनाए बिना ही दी जा सकती है।

बैंकिंग से संबन्धित नीतियाँ

खुदरा प्रत्यक्ष योजना : भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों में खुदरा सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए बाजार निर्माण योजना अधिसूचित किए

भारतीय रिजर्व बैंक ने अब खुदरा प्रत्यक्ष श्रेष्ठ (RDG) खाता धारकों को कीमतें/भाव उपलब्ध कराते हुये बाजार निर्माण योजना अधिसूचित कर दी है, ताकि वे भारतीय रिजर्व बैंक खुदरा प्रत्यक्ष योजना के अधीन प्रतिभूतियाँ खरीद और बेच सकें। गौण बाजार में चलनिधि उपलब्ध कराते हुये इसे सुगम बनाने के लिए एक ऐसी बाजार निर्माण व्यवस्था अधिसूचित की गई है जिसमें प्राथमिक व्यापारियों (PDs) को तयशुदा लेनदेन प्रणाली –आदेश मिलान (NDS-OM) प्लेटफार्म (विषम लाट और भावों हेतु अनुरोध) पर बाजार के कामकाज के पूरे समय के दौरान उपस्थित रहना होगा तथा खुदरा प्रत्यक्ष श्रेष्ठ (RDG) खाता धारकों से प्राप्त खरीद/बिक्री अनुरोधों पर कार्रवाई करनी होगी। प्राथमिक व्यापारी खुदरा प्रत्यक्ष योजना के तहत किए गए खुदरा प्रत्यक्ष श्रेष्ठ खाता धारकों के अपने ग्राहक को जानिए (KYC) सत्यापन पर निर्भर करेगे।

भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर-वित्तीय छोटे कारबार वाले ग्राहकों की जमाराशियों के लिए प्रारम्भिक सीमा बढ़ाकर बैंकों के चलनिधि व्याप्ति अनुपात को अनुरक्षित रखे

बैंकों के चलनिधि व्याप्ति अनुपात (LCR) को बनाए रखने के एक अभियान में भारतीय रिजर्व बैंक ने गैर वित्तीय छोटे कारबार वाले ग्राहकों द्वारा रखी गई जमाराशियों और निधियों के अन्य विस्तारों के लिए प्रारम्भिक सीमा को 5 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 7.5 करोड़ कर दिया है। उक्त परिवर्तन चलनिधि जोखिम का अधिक प्रभावी विधि से प्रबंधन करने में बैंकों की सहायता करने से संबन्धित बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (BCBS) के मानक पर आधारित दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए किया गया है।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

भारतीय रिजर्व बैंक ने बड़े आकार वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- भारतीय ऋण कम्पनियों को आढ़त व्यवसाय करने की अनुमति दी

संशोधित आढ़त विनियमन अधिनियम, 2011 के अधीन नए विनियमन जारी करते हुये भारतीय रिजर्व बैंक ने 1,000 करोड़ रुपए और उससे अधिक के आस्ति आकार वाली जमा न स्वीकार करने वाली सभी मौजूदा गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी- निवेश और ऋण कंपनियों (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी –भारतीय ऋण कम्पनियों) को कुछेक शर्तों के अधीन आढ़त व्यवसाय आरंभ करने की अनुमति

दे दी है। अन्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी – भरीय ऋण कम्पनियाँ भी अपने आप को गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी –आढ़तिया के रूप में पंजीकृत करवा कर आढ़त व्यवसाय आरंभ कर सकती हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक ने व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली को आढ़तियों की ओर से केंद्रीय रजिस्ट्री के पास लेनदेनो को प्रस्तुत करने की अनुमति दी

आढ़त विनियमन अधिनियम, 2011 को संशोधित करके आढ़त व्यवसाय करने वाली कंपनियों के प्रसार-क्षेत्र को व्यापक बनाये जाने के अनुसरण में व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS) को आढ़तियों की ओर से प्राप्यराशियों के समनुदेशन के विवरण केंद्रीय रजिस्ट्री के पास प्रस्तुत करने की अनुमति दे दी गई है। यह कार्य परिचालनात्मक कुशलता प्राप्त करने हेतु किया गया है। उक्त अधिनियम द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों/अधिकारों को ध्यान में रखते हुये शीर्ष बैंक ने पंजीकरण का प्रमाणपत्र दिये जाने की रीति निर्धारित किए जाने और व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली द्वारा प्राप्यराशियों के समनुदेशन प्रस्तुत किए जाने के लिए विनियम तैयार किया है। प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली के माध्यम से वित्तपोषित व्यापारिक प्राप्यराशियों के समनुदेशन के विवरण व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली द्वारा केंद्रीय रजिस्ट्री के पास 10 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर दिये जाने होंगे।

विनियामक के कथन

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोविड पश्चात किए गए उपायों के अच्छे परिणाम आ रहे हैं; बैंक ऋण में वृद्धि हो रही है; मुद्रास्फीति में कमी आ रही है : भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर

वार्षिक सी॰ डी॰ देशमुख स्मरक व्याख्यान में बोलते हुये भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर डा॰ माइकल पात्रा ने कहा है कि विद्यमान कोविड-पश्चात वाले युग में निजी उपभोग और निवेश कार्य प्रगति पर है की स्थिति में बना हुआ है, जबकि आजीविका कि बहाली और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का पुनरुज्जीवन आरंभ किया गया एक दुर्जेय कार्य है। तथापि, 27 मार्च, 2019 से वैश्विक महामारी वाली अवधि के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों ने ''भारतीय अर्थव्यवस्था का कायापलट करने में उल्लेखनीय योगदान किया है।''

निकट भविष्य के बारे में डा॰ पात्रा ने कहा कि ''वैश्विक महामारी द्वारा भविष्य को आकार देने का क्रम जारी है, किन्तु भारतीय रिजर्व बैंक सुसज्जित एवं आने वाली कठिनाइयों से निपटने हेतु पूरी तरह तैयार है। उक्त वैश्विक महामारी से मिलने वाली नसीहत आत्मसात की जाएगी तथा भारतीय रिजर्व बैंक और अधिक सुदृढ़ होगा और पहले की अपेक्षा अधिक आघात-सह बनेगा एवं वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुये मूल्य-स्थिरता वाले अधिदेश के लिए प्रतिबद्ध रहेगा।''

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की मुख्य बातें

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा दिसंबर, 21 में जारी किए गए आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कुछेक मुख्य आर्थिक संकेतकों के कार्य-निष्पादन इसके नीचे दर्शाये गए हैं :

- 2021-22 में 9.2% के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) वृद्धि की आशा है।
- 2021-22 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में 3.9% की वृद्धि की आशा है और सेवा क्षेत्र में 8.2% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- दिसंबर, 2021 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति वर्षानुवर्ष 5.6% रही और थोक मूल्य सूचकांक (WPI) मुद्रास्फीति दो अंकों में बनी रही।

- जुलाई, 2021 से सकल मासिक माल और सेवा कर (GST) वसूलियों का 1 लाख रुपए के स्तर को पार कर जाने का क्रम निरंतर रूप से जारी रहा।
- 31 दिसंबर, 2021 के दिन बैंक ऋण वृद्धि का स्तर 9.2% रहा।
- 75 प्रारम्भिक सार्वजनिक प्रस्तावों (IPOs) के जरिये 89,066 करोड़ रुपए जुटाये गए जो पिछले दशक में किसी भी वर्ष के स्तर से उल्लेखनीय रूप से अधिक है।
- 2022-23 में सकल घरेलू उत्पाद में वास्तविक रूप से 8-8.5% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- मांग पक्ष में उपभोग में 7.0%, सकल स्थिर पूंजी निर्माण (GFCF) में 15%, निर्यात में 16.5% और आयात में 29.4% की वृद्धि होने का अनुमान है।
- केंद्रीय सरकार से राजस्व प्राप्तियों (अप्रैल से नवंबर, 2021 तक) में 2021-22 के बजट अनुमानों (2020-21 की अनंतिम वास्तविक रकम से अधिक) 9.6% के समक्ष 67.2% (वर्षानुवर्ष) वृद्धि हुई।

नयी नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
अजय कुमार चौधरी	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
दीपक कुमार	कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक
अतुल कुमार गोयल	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, पंजाब नैशनल बैंक
सोमा शंकर प्रसाद	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूको बैंक

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियाँ

मद	28 जनवरी, 2022 के दिन करोड रुपए	28 जनवरी, 2022 के दिन मिलियन अमरीकी डालर
1. **कुल प्रारक्षित निधियाँ**	4727298	629755
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4249350	566077
1.2 सोना	296461	39493
1.3 विशेष आहरण अधिकार	142706	19011
1.4 अंतराष्ट्रीय मुद्रा कोष में प्रारक्षित निधि की स्थिति	38780	5174

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

फरवरी, 2022 माह के लिए लागू अनिवासी विदेशी मुद्रा (बैंक) जमाराशियों के लिए लागू होने वाली वैकल्पिक संदर्भ दरों (ARRs) की न्यूनतम दरें

मुद्रा	दरें
अमरीकी डालर	0.04
जीबीपी	0.1957
यूरो	-0.573
जापानी येन	-0.021
कनाडाई डालर	0.16
आस्ट्रेलियाई डालर	0.1
स्विस फ्रैंक	-0.711974
न्यूजीलैंड डालर	0.75
स्वीडिश क्रोन	-0.113
सिंगापुर डालर	0.4588
हांगकांग डालर	0.09346
म्यामर रुपया	1.73

स्रोत : www.fedai.org.in

शब्दावली

व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली (TReDS)

व्यापारिक प्राप्यराशि भुनाई प्रणाली एकाधिक वित्तपोषकों के जरिये सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) की व्यापारिक प्राप्यराशियों के वित्तीयन/की भुनाई को सुगम बनाने हेतु एक इलेक्ट्रोनिक प्लेटफार्म होती है। ये प्राप्यराशियां सरकारी विभागों एवं

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) सहित कार्पोरेटों और अन्य क्रेताओं से प्राप्य हो सकती हैं।

वित्तीय क्षेत्र की बुनियादी जानकारी

कसौटी अनुपात (Acid Test Ratio)

सामान्यतया त्वरित अनुपात (Quick ratio) के रूप में ज्ञात कसौटी अनुपात में किसी फर्म के तुलनपत्र के आंकड़ों का उपयोग इस बात के संकेतक के रूप में किया जाता है कि उसके पास उसकी अल्पावधिक देयताओं को चुकाने हेतु पर्याप्त अल्पावधिक आस्तियां हैं या नहीं। इसमें उन आस्तियों को हिसाब में नहीं लिया जाता जिनका परिसमापन करने में समय लगता हो या जिनका परिसमापन कठिन हो।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

फरवरी, 2022 माह के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथियाँ	स्थान
विदेशी मुद्रा परिचालन	14 से 16 फरवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
तुलनपत्र वाचन और अनुपात विश्लेषण	14 से 16 फरवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
अपने ग्राहक को जानिए, धन शोधन निवारण और आतंकवाद के वित्तीयन का मुक़ाबला	21 से 23 फरवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
प्रमाणित लेखांकन एवं लेखा-परीक्षा व्यावसायिक	22 से 24 फरवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित
तुलनपत्र वाचन और अनुपात विश्लेषण	23 से 25 फरवरी, 2022 तक	प्रौद्योगिकी पर आधारित

संस्थान समाचार

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम और डिप्लोमा/ प्रमाणपत्र परीक्षाओं का स्थगन

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी परीक्षाएँ जिन्हें कोविड प्रतिबंधों के कारण स्थगित कर दिया गया था, अब 26 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च 2022 को आयोजित की जाएंगी। इसके अतिरिक्त, डिप्लोमा/प्रमाणपत्र परीक्षाएँ जिन्हें 20 फरवरी, 27 फरवरी और 6 मार्च, 2022 को आयोजित किया जाना था, अब स्थगित कर डी गई हैं। संशोधित तिथियाँ शीघ्र ही घोषित की जाएंगी।

आत्म-समगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रम के उत्तीर्णन मानदंड में संशोधन

डिजिटल बैंकिंग और बैंकिंग में नीतिशास्त्र में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमों के लिए आत्म-समगामी ई-शिक्षण विधि के अधीन अंतिम मूल्यांकन/ परीक्षण हेतु उत्तीर्णन अंकों को 70 से संशोधित करके 60 कर दिया गया है। यह 1 मार्च, 2022 को या उसके बाद आत्म-समगामी ई-शिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए कराये जाने वाले पंजीकरणों पर प्रभावी होगा।

आईआईबीएफ ने बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक का विमोचन किया

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स ने दिसंबर, 2021 तक अद्यतन की हुई

''बैंकिंग एंड फाइनैन्स इयरबुक'' का विमोचन किया। यह सभी महत्वपूर्ण घटनाओं, प्रवृत्तियों, विशेषज्ञों के विचारों और बैंकिंग एवं वित्त के विषय-क्षेत्र के विभिन्न कार्य-क्षेत्रों में हुये विनियामक परिवर्तनों की एक ऐसी व्यापक सार-पुस्तिका है जिसमें पाठक को हितकर वाचन अनुभव दिलाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिये गए महत्वपूर्ण व्याख्यानों के उद्धरणों, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स के जर्नल बैंक क्वेस्ट में प्रकाशित चुनिन्दा लेखों का समावेश है। उक्त पुस्तक पेपरबैक के रूप में और एक उद्दीपक (kindle) संस्करण, दोनों ही रूपों में अमैजान पर उपलब्ध है। यह पुस्तक हमारे प्रकाशक मैसर्स टैक्समैन पब्लिकेशन्स (प्राइवेट) लिमिटेड के खुदरा बिक्री केन्द्रों पर भी उपलब्ध है।

प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा व्यावसायिक पाठ्यक्रम की शुरूआत

इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स (IIBF) ने भारतीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (National Institute of Securities Markets) और राष्ट्रीय बीमा अकादमी (NIA) के सहयोग से 11 फरवरी, 2022 को प्रमाणित बैंकिंग, वित्तीय सेवाएँ और बीमा (BFSI) व्यावसायिक पाठ्यक्रम की प्रौद्योगिकीय विधि से शुरूआत की। यह पाठ्यक्रम अनूठा एवं बैंकिंग, वित्तीय सेवाओं और बीमा

क्षेत्र में आजीविका अपनाने की इच्छा रखने के आकांक्षियों को उपलब्ध कराई जाने वाली अपने ढंग की एक विशिष्ट पहलकदमी है। यह 9 महीनों की अवधि में पूरा किए जाने वाला 187 घंटों का एक ई-शिक्षण कार्यक्रम है। उदघाटन भाषण संबन्धित संस्थानों के पदाधिकारियों द्वारा दिये गए तथा विशेष व्याख्यान भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यपालक श्री सुनील मेहता और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यजीत त्रिपाठी द्वारा दिये गए। उक्त कार्यक्रम में महाविद्यालयों और बैंकरों की अच्छी-ख़ासी संख्या में उपस्थिति रही।

जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज़ (JBIMS) के साथ सहयोग

संस्थान ने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए रणनीतिक नेतृत्व पर उन्नत कार्यक्रम को संयुक्त रूप से प्रमाणित करने हेतु जमनालाल बजाज इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट स्टडीज़ के साथ सहयोग किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य संगठन के भविष्य के लिए वहनीय विजन सृजित करने हेतु रणनीतिक चिंतन एवं सामर्थ्य को बढ़ाना है। उक्त कार्यक्रम केवल सप्ताहांत में (शनिवारों और रविवारों कॉ) संचालित किया जाने वाला 30 घंटो का (5 दिवसीय) कार्यक्रम है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट देखें।

जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी – संशोधित पाठ्यक्रम की शुरूआत

घटनाओं से सामंजस्य बनाए रखने तथा इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग एण्ड फ़ाइनैन्स द्वारा उपलब्ध कराये जा रहे मुख्य पाठ्यक्रमों में अधिकाधिक मूल्य-योजन सुनिश्चित करने के लिए जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के पाठ्यक्रमों को अधिक संकल्पनात्मक एवं सम-सामयिक बनाए रखने के लिए उन्हें पुनरसंरचित कर दिया गया है। संशोधित पाठ्यक्रमों के अधीन जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ नवंबर/दिसंबर, 2022 और उसके बाद अथवा किसी भी स्थिति में अधिकतम मई/जून, 2023 से आयोजित किए जाने का अस्थाई तौर पर निर्णय लिया गया है। पुराने पाठ्यक्रम (वर्तमान पाठ्यक्रम) के अनुसार जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी के अधीन अंतिम परीक्षाएँ नवंबर/ दिसम्बर, 2022 दौरान आयोजित की जाएंगी, जिसके बाद उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मई/जून, 2023 के बाद से जेएआईआईबी/डीबीएण्डएफ/एसओबी/सीएआईआईबी परीक्षाएँ केवल संशोधित पाठ्यक्रमों के अनुसार ही आयोजित की जाएंगी। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखेँ।

सूक्ष्म एवं स्थूल अनुसंधान

सूक्ष्म एवं स्थूल अनुसंधान के लिए विषयों को अंतिम रूप दे दिया गया है और उनके विवरण संस्थान की वेबसाइट पर डाल दिये गए हैं। इस योजना के अधीन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 28 फ़रवरी, 2022 है। अधिक विवरण के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.iibf.org.in देखेँ।

सब के लिए ई-शिक्षण सुविधा

संस्थान ने "सब के लिए ई-शिक्षण" की ऐसी सुविधा की शुरूआत की है जिसमें सदस्यता की स्थिति या परीक्षा हेतु पंजीकरण की स्थिति चाहे जैसी भी क्यों न हो, कोई भी व्यक्ति संस्थान द्वारा तैयार किए गए बैंकिंग एवं वित्त से संबन्धित विविध सम- सामयिक विषयों पर ई-शिक्षण माँड्यूल का लाभ उठा सकता है। अधिक जानकारी के लिए www.iibf.org.in देखें।

आगामी अंक के लिए बैंक क्वेस्ट की विषय-वस्तु

बैंक क्वेस्ट के जनवरी - मार्च, 2022 तिमाही के लिए के आगामी अंक हेतु विषय-वस्तु है: "दबावग्रस्त आस्तियों का प्रभावी समाधान (Effective resolution of stressed assets)"

परीक्षाओं के लिए दिशानिर्देशों /महत्वपूर्ण घटनाओं की निर्धारित तिथि

संस्थान में इस बात की जांच करने के उद्देश्य से कि अभ्यर्थी अपने - आपको वर्तमान घटनाओं से अवगत रखते हैं या नहीं प्रत्येक

परीक्षा में कुछ प्रश्न हाल की घटनाओं/ विनियामक/कों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में पूछे जाने की परंपरा है। हालांकि, घटनाओं/ दिशानिर्देशों में प्रश्नपत्र तैयार किए जाने की तिथि से और वास्तविक परीक्षा तिथि के बीच की अवधि में कुछ परिवर्तन हो सकते हैं। इन मुद्दों का प्रभावी रीति से **समाधान** करने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि

(i) संस्थान द्वारा फरवरी, 2022 से जुलाई, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक//कों द्वारा जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 31 दिसम्बर, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

(ii) संस्थान द्वारा अगस्त, 2021 से जनवरी, 2022 तक की अवधि के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के संबंध में प्रश्नपत्रों में समावेश के लिए विनियामक/कों द्वारा जारी अनुदेशों/ दिशानिर्देशों और बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में 30 जून, 2021 तक की महत्वपूर्ण घटनाओं पर ही विचार किया जाएगा।

नयी पहलकदमी

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान के पास मौजूद उनके ई-मेल पते अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल के जरिये प्राप्त करने हेतु अपनी सहमति भेज दें।

बाजार की खबरें

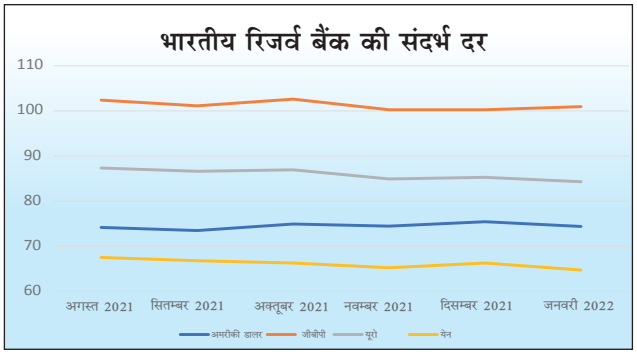

स्रोत: एफबीआईएल

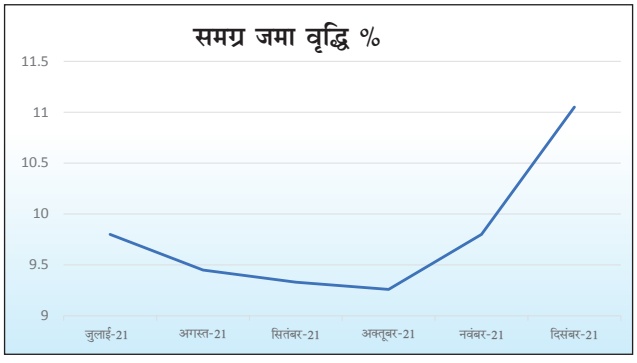

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2022

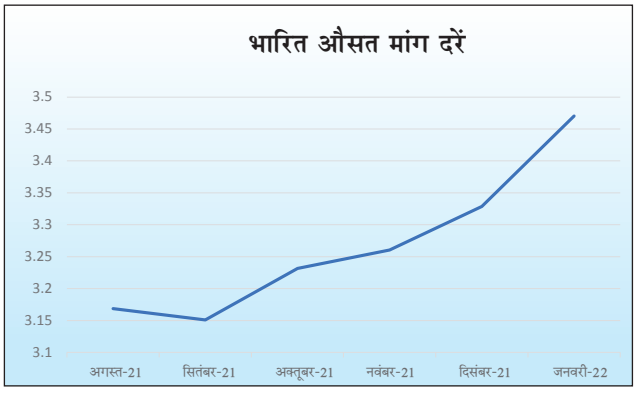

स्रोत : भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

स्रोत भारतीय रिजर्व बैंक

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

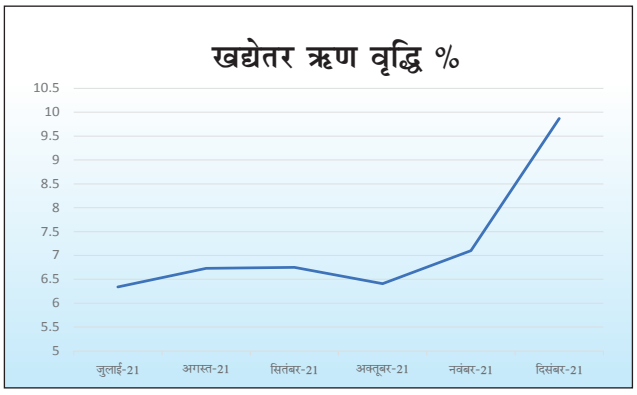

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समशोधन निगम लिमिटेड, जनवरी, 2022

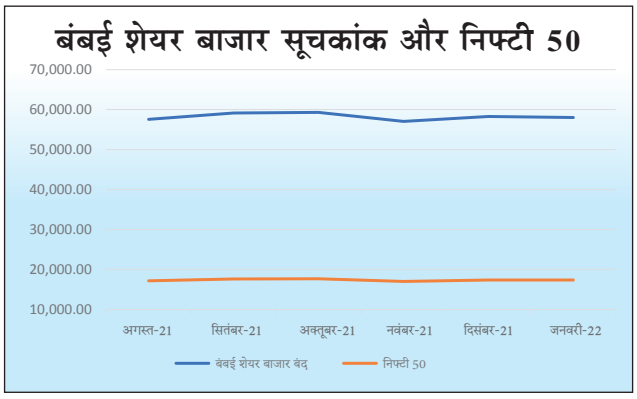

स्रोत : बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

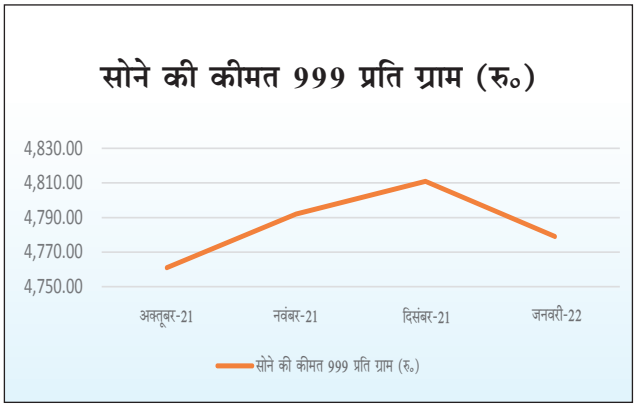

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

बिश्व केतन दास द्वारा मुद्रित, बिश्व केतन दास द्वारा इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स की ओर से प्रकाशित तथा आनलुकर प्रेस, 16 सासुन डाक, कोलाबा, मुंबई - 400 005 में मुद्रित एवं इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स, कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070 से प्रकाशित।
संपादक : बिश्व केतन दास

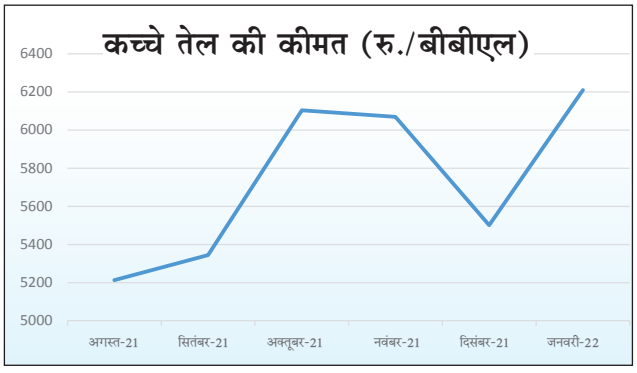

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स

कोहिनूर सिटी, कामर्शियल-II, टावर-1, 2री मंजिल, किरोल रोड, कुर्ला (पश्चिम), मुंबई - 400 070
टेलीफोन : 91-22-6850 7000
ई-मेल : admin@iibf.org.in.
वेबसाइट : www.iibf.org.in